



# 4 P M सांध्य दैनिक



हर बार जब मैं एक बच्चे को मुक्त कराता हूँ, मुझे लगता है ये भगवान के कुछ करीब है।

मूल्य ₹ 3/-

-कैलाश सत्यार्थी

जिद...सच की

www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor\_Sanjay YouTube @4pm NEWS NETWORK

वर्ष: 8 • अंक: 229 • पृष्ठ: 8 • लखनऊ, बुधवार, 28 सितम्बर, 2022

लता दीदी के स्वरों में गूंजती है... 8 लोक सभा चुनाव से पहले प्रदेश... 3 बिहार में भाजपा को नहीं जीतने... 7

## नरेश उत्तम फिर बने सपा के प्रदेश अध्यक्ष, अखिलेश बोले, सांप्रदायिक ताकतों को सत्ता से करेंगे बाहर

फोटो: सुमित कुमार



» सपा सरकार के समय किए गए कामों से आगे नहीं बढ़ी भाजपा

» झंडारोहण के साथ शुरू हुआ सपा का दो दिवसीय सम्मेलन

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। सपा का दो दिवसीय सम्मेलन आज रमाबाई मैदान में झंडारोहण के साथ शुरू हुआ। सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में मंच से नरेश उत्तम पटेल को फिर से प्रदेश अध्यक्ष चुनने की घोषणा की गई। सपा के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने निर्वाचन प्रक्रिया के तहत एकमात्र नामांकन आने की वजह से नरेश उत्तम को प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया। वहीं सम्मेलन को संबोधित करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिर्फ

सपा कार्यकर्ताओं में दिखा जोश

राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय सम्मेलन को लेकर सपा नेताओं में जबरदस्त जोश है। पार्टी कार्यालय से लेकर रमाबाई आंबेडकर मैदान तक सड़क के दोनों तरफ सपा के झंडे लगाए गए हैं। जगह-जगह बैनर पोस्टर के साथ कटआउट भी लगाए गए हैं। ज्यादातर कटआउट पर सिर्फ अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। कुछ में सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और आनन खां, प्रो रामगोपाल सहित अन्य स्थानीय नेताओं की तस्वीर लगी है लेकिन ये कटआउट इस बात की तस्वीर कर रहे हैं कि यह सम्मेलन पूरी तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर केंद्रित है।

सपा ही सांप्रदायिक ताकतों को रोक सकती है। हम समाज को बांटने वाली ताकतों को सत्ता से बाहर करेंगे।

अखिलेश ने कहा कि सरकारी नौकरियों में बहुजन को मिले आरक्षण के संवैधानिक अधिकार से सरकार छेड़छाड़ कर रही है। सरकार जानबूझ कर सरकारी संस्थाएं ध्वस्त कर रही है ताकि व्यवस्थाओं का निजीकरण किया जा सके। सपा ने 2019 के लोक सभा

ये रहे मौजूद

सम्मेलन के मंच पर स्वामी प्रसाद मोदी, प्रो. रामगोपाल यादव, नरेश उत्तम पटेल, राजेंद्र चौधरी, रामजी लाल सुमन, रामगोविंद चौधरी, किरणमय नंदा सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे।

» आरक्षण के संवैधानिक अधिकार से छेड़छाड़ कर रही सरकार

चुनाव में बहुजन समाज की ताकत को एक मंच पर लाने का प्रयास किया। उन्होंने सपा सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और कहा कि हम जब सत्ता में आएंगे तो किसानों के लिए काम करेंगे। सर्वसमाज को शिक्षित करेंगे। सपा सरकार ने जो काम किया था भाजपा उससे आगे कुछ भी नहीं कर पाई है। उन्होंने मेट्रो निर्माण और नदियों की सफाई आदि का मुद्दा उठाया।

## टेरर फंडिंग पर केंद्र का एक्शन, पीएफआई पांच साल के लिए बैन

सहयोगी संगठन भी गैरकानूनी घोषित, अधिसूचना जारी

» ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद गृह मंत्रालय ने की कार्रवाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। टेरर फंडिंग मामले में केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उससे जुड़े संगठनों पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इन संस्थाओं को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने बैन को लेकर अधिसूचना जारी की है।

अधिसूचना के मुताबिक पीएफआई के कुछ संस्थापक सदस्य प्रतिबंधित संगठन सिमी के नेता हैं। उसके जमात-उल-



मुजाहिदीन बांग्लादेश से भी लिंक हैं। पीएफआई के आईएसआईएस जैसे आतंकी समूहों से भी संबंध मिले हैं। पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन या मोर्चे गुप्त एजेंडे के तहत एक समुदाय को कट्टर बनाकर देश में असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। इसके लिए पीएफआई के कुछ सदस्य अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों में शामिल हो गए थे। जो देश की अखंडता,

हम सांप्रदायिकता के खिलाफ: जयराम रमेश



पीएफआई पर लगे प्रतिबंध पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से सभी प्रकार की सांप्रदायिकता के खिलाफ रही है। कांग्रेस की नीति हमेशा से बिना किसी डर के बिना किसी समझौते के सांप्रदायिकता से लड़ने की रही है।

संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ है। बता दें कि पीएफआई के ठिकानों पर 22 और 27 सितंबर को छापेमारी की गई थी। 22 सितंबर को 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था जबकि कल हुई छापेमारी में 170 से अधिक लोगों को हिरास्त में लिया गया।

## शराब घोटाले में समीर महेंद्र गिरफ्तार केजरीवाल बोले, अब सिसोदिया की बारी

» इंडोस्प्रीट ग्रुप के प्रबंध निदेशक हैं समीर, कल विजय नायर की हुई थी गिरफ्तारी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉड्रिंग मामले में इंडोस्प्रीट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी ने महेंद्र की गिरफ्तारी मनी लॉड्रिंग के आरोप में की है। ईडी दिल्ली की आप सरकार की वापस ली गई आबकारी नीति की जांच कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस मामले में अगले हफ्ते सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने की तैयारी हो रही है।

समीर महेंद्र पर आरोप है कि वे आबकारी नीति को बनाने और उसे लागू करवाने में सक्रिय थे। इसके पहले सीबीआई ने कथित शराब घोटाले में विजय नायर को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि नायर के जरिए एक शराब फर्म के मालिक से रिश्वत ली गई थी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, अब ये अगले हफ्ते मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। इनको डर लग रहा है कि गुजरात इनके हाथ से निकल रहा है इसलिए ये हमारे पीछे पड़े हैं।



# योगी सरकार लाई नई एमएसएमई नीति, मिलेगी ब्याज में छूट एससी-एसटी और महिला उद्यमियों को ब्याज में 60 प्रतिशत छूट

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने नई एमएसएमई नीति-2022 को मंजूरी देकर इस सेक्टर के प्रोत्साहन के लिए खजाना खोल दिया है। निवेश पर 25 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी और लिए गए ऋण पर 50 प्रतिशत तक ब्याज में छूट (उपादान) का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 10 एकड़ से अधिक के एमएसएमई पार्क स्थापित करने के लिए भूमि खरीदने पर स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। इतना ही नहीं, बहिष्कार के निस्तारण के लिए कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लान (सीईटीपी) के लिए 10 करोड़ रुपये तक की वित्तीय मदद भी दी जा सकेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 को अनुमोदित कर दिया है। इसमें किसी तरह का संशोधन मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद ही किया जा सकेगा। नई नीति के तहत स्थापित होने वाले नए एमएसएमई उद्यमों को पूंजीगत उपादान के रूप में 10 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक उपादान उपलब्ध कराया जा सकेगा। पूंजीगत उपादान (छूट) प्लॉट व मशीनरी आदि पर निवेश



## ग्राम सभा की 5 एकड़ भूमि उद्योगों के लिए मिलेगी

10 एकड़ से अधिक के एमएसएमई पार्क स्थापित करने के लिए भूमि खरीद पर 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट और लिए गए ऋण पर 7 वर्षों तक 50 प्रतिशत ब्याज उपादान (अधिकतम दो करोड़ रुपये) उपलब्ध कराया जाएगा। औद्योगिक आस्थानों में भूखंडों और शेडों के आवंटन की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए 5 एकड़ या उससे अधिक ग्राम सभा की भूमि पुनर्बांटी कर निशुल्क उद्योग निदेशालय को स्थानांतरित की जाएगी। विभाग भूखंडों का विकास करते हुए जिलाधिकारी के सर्किल रेट पर आवंटन करेगा। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 5 किमी की दूरी के अंतर्गत औद्योगिक आस्थानों के विकास के माध्यम से एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

## अयोध्या में एसटीपी बनाने के निशुल्क 10 एकड़ जमीन देगा आवास विभाग

अयोध्या में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) लगाने में आ रही जमीन की दिक्कत को दूर कर दिया है। सरकार ने एसटीपी लगाने के लिए 10 एकड़ नजूल भूमि को नगर विकास विभाग को देने का फैसला किया है। नगर विकास विभाग को यह भूमि निशुल्क दी जाएगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। बता दें कि मौजूदा समय में अयोध्या का विकास सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। जिस तरह से रामनगरी का विकास का खाका तैयार किया जा रहा है, उसे देखते हुए भविष्य में अयोध्या की आबादी में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए शहर में अवस्थापना की कई विकास परियोजनाएं चल रही हैं। इसी कड़ी में शहर की सीवर व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही सीवेज शोधन के लिए यहां एक एसटीपी लगाने का भी काम होना है, लेकिन एसटीपी लगाने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। एसटीपी लगाने की जिम्मेदार अयोध्या नगर निगम को सौंपा गया है।

## दो वर्ष बाद ला सकेंगे क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अब दो वर्ष बाद ही लाया जा सकेगा। अविश्वास प्रस्ताव के लिए दो तिहाई सदस्यों की सहमति भी अनिवार्य होगी। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 15 एवं 28 में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया। पंचायतीशक्ति विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक जिला पंचायत अध्यक्ष और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ निर्वाचित होने के एक वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों के 51 फीसदी की सहमति होना आवश्यक है।

पर मिलता है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्रों में उपादान की यह सीमा 15-25 प्रतिशत तक और मध्यांचल व पश्चिमांचल में 10-20 प्रतिशत तक होगी। एससी-

एसटी और महिला उद्यमियों के लिए दो प्रतिशत अधिक छूट दी जाएगी। प्रदेश में स्थापित होने वाले नए सूक्ष्म उद्योगों के लिए पूंजीगत ब्याज उपादान के तहत ऋण

पर देय वार्षिक ब्याज पर 50 प्रतिशत छूट मिलेगी। एससी-एसटी और महिला उद्यमियों के लिए यह ब्याज उपादान 60 प्रतिशत तक होगा नीति के अनुसार,

एमएसएमई इकाइयों को अधिक से अधिक स्रोतों से क्रेडिट उपलब्ध कराने के लिए स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

## प्रदेश में जल्द आयोजित होगी विधायक खेलकूद प्रतियोगिता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार ने प्रतिभावान खिलाड़ियों को शासकीय सेवा का मौका देने के लिए दो प्रतिशत सीटें आरक्षित की हैं तो पुलिस में 500 से अधिक पदों पर नियुक्ति शुरू हो गई है और अब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को आवागमन के लिए रेलवे की एसी थी टियर कोच की सुविधा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी ने गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने जा रहे होनहार खिलाड़ियों को उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। खेलों के इस राष्ट्रीय कुंज में भाग लेने जा रहे 462 सदस्यीय दल को टीमवर्क का मंत्र देते हुए मुख्यमंत्री ने सभी के शानदार प्रदर्शन के प्रति विश्वास जताया।

## नीति आयोग की तर्ज पर राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन

- » सीएम होंगे स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के अध्यक्ष
- » 50 वर्ष पूर्व गठित राज्य योजना आयोग का अस्तित्व खत्म

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। योगी सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर राज्य योजना आयोग के पुनर्गठन का निर्णय करते हुए इसे स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन (एसटीसी) का नाम दिया है। एसटीसी राज्य की नीतियों के निर्धारण के लिए थिंक टैंक और ज्ञान के भंडार के रूप में काम करेगा। राज्य के भौतिक, वित्तीय और जन संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए सुझाव देगा। अगले पांच वर्षों में उग्र की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डालर का आकार देने की दिशा में भी काम करेगा।

एसटीसी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) लोक प्रशासक/ प्रमुख सचिव या



उससे उच्च स्तर का सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारी होगा। इसमें एक अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी होगा जो विशेष सचिव नियोजन के स्तर का अधिकारी होगा। एसटीसी सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली में परिणाम आधारित कार्यपद्धति को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा। राज्य के विकास के लिए नीतियों में नए ज्ञान, दक्षताओं और नवाचारों का भी समावेश करेगा। सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के अवरोधों को चिन्हित कर उन्हें दूर करने के सुझाव देगा। कार्यक्रमों और परियोजनाओं को सार्वजनिक निजी सहभागिता के आधार पर आगे बढ़ाने के लिए सलाह देगा।

## कहीं नहीं गए हैं आजम खां : तजीन खां

» मेरे पति बीमार हैं, पिता की तीमारदारी में हैं  
अब्दुल्ला आजम

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। सपा नेता आजम खां की पत्नी डॉ. तजीन फात्मा ने कहा कि उनके पति बीमार हैं और दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं। अब्दुल्ला वहां पर अपने पिता की तीमारदारी कर रहे हैं। यह बात पूरी तरह से गलत है कि आजम खां और अब्दुल्ला कहीं चले गए हैं और उनके नाम लुक आउट नोटिस जारी होने वाला है। डॉ. फात्मा ने कहा है कि नौ सितंबर को जांच में पता चला था कि मेरे पति के दिल में ब्लॉकेज है।

इसके बाद उनकी एंजियोग्राफी हुई और स्टेंट डाले गए। 15 सितंबर को उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन बेचैनी और सीने



में दर्द होने की शिकायत पर उनको दोबारा 22 सितंबर को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब्दुल्ला भी वहीं रहकर अपने पिता की देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे पति कानून का पालन करने वाले और न्याय पसंद व्यक्ति हैं। बीमारी की वजह से वह दबाव झेलने की स्थिति में नहीं हैं। यदि किसी विवेचना में उनकी जरूरत है तो वह स्वस्थ होने के बाद पूरा सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा है कि उनके बीमार होने की जानकारी कोर्ट को भी

दे दी गई है। डॉ. फात्मा इस बात को पूरी तरह से गलत बताया कि आजम खां और अब्दुल्ला ने अपनी सुरक्षा वापस कर दी है। रामपुर एसपी अशोक मीर ने कहा है कि पुलिस को पता नहीं है कि आजम खां कहां हैं। आजम खां और अब्दुल्ला आजम ने अपने गनर वापस लौटा दिए हैं। सुरक्षा कर्मियों से कहा गया था पता करो कि वो लोग कहां तो उन्होंने बताया कि कोई जानकारी नहीं मिल रही है। एसपी ने इस संभावना से इनकार किया कि आजम खां के खिलाफ कोई लुक आउट नोटिस जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें कोर्ट से जो आदेश मिलेगा उसके मुताबिक हम कार्रवाई करेंगे। वैसे उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि आजम खां को गिरफ्तार किया जा सकता है।

सोशल मीडिया  
**बामुलाहिजा**  
कार्टून: हसन जैदी

## मुंबई के व्यापारी ने हड़पे भाजपा सांसद रवि किशन के सवा तीन करोड़

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। शहर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद व फिल्म अभिनेता रवि किशन शुक्ला के 3.25 करोड़ रुपये मुंबई के व्यापारी ने हड़प लिए हैं। आरोप है कि सांसद ने दस वर्ष पहले व्यापारी को रुपये उधार दिए थे। व्यापारी पर रुपये लौटाने का दबाव बनाया तो चेक थमा दिए, जो कि बाउंस हो गए। सांसद की शिकायत पर केंद्र पुलिस ने मुंबई के व्यापारी जैन जितेंद्र रमेश के खिलाफ रुपये हड़पने का केस दर्ज कर लिया है।

सांसद रवि किशन ने पुलिस अधिकारियों को दिए प्रार्थना पत्र में लिखा है कि वर्ष 2012 में ईस्ट मुंबई के कमला पाली बिल्डिंग निवासी जैन जितेंद्र रमेश को 3.25 करोड़ रुपये दिए थे। जब रुपये वापस मांगे गए तो वह आनाकानी करने लगे। दबाव बनाया गया तो 34-34 लाख रुपये के 12 चेक दे दिए। यह चेक मुंबई के विले पार्ले, पीएम रोड स्थित

टीजेएचडी सहकारी बैंक लिमिटेड के थे। सात दिसंबर 2021 को 34 लाख रुपये का चेक एसबीआई की बैंक रोड स्थित शाखा में जमा कराया गया, लेकिन बैंक खाते में रुपये नहीं आए। 16 फरवरी 2022 को बैंक के अधिकारियों ने पत्र लिखकर बताया कि जिस बैंक खाते का चेक दिया गया, उसमें रुपये ही नहीं हैं। लिहाजा, चेक बाउंस हो गया। इस सिलसिले में व्यापारी जैन जितेंद्र रमेश से बात भी की गई, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल सका। चेक बाउंस होने के बाद से ही अपने रुपये वापस मांग रहे हैं, लेकिन व्यापारी तैयार नहीं हैं। इससे मानसिक रूप से परेशान हैं।



**MEDISHOP**  
PHARMACY & WELLNESS  
24 घंटे  
दवा अब आपके फोन पर उपलब्ध

+91- 8957506552  
+91- 8957505035

गोमती नगर का सबसे बड़ा  
**मेडिकल स्टोर**

हमारी विशेषताएं

- 10% DISCOUNT
- 5% CONSULTANT

जहां आपको मिलेगी हर प्रकार की दवा भारी डिस्काउंट के साथ

1. सायं 4.00 बजे से 6.00 बजे रात्रि तक चिकित्सक उपलब्ध।  
2. 12.00 बजे से 8.00 बजे रात्रि तक ट्रेंड नर्स उपलब्ध।

- बीपी-शुगर चेक करवायें
- हर प्रकार के इन्जेक्शन लगावायें।

पशु-पक्षियों की दवा एवं उनका अन्य सामान उपलब्ध।

स्थान: 1/758 - ए, भूतल, सेक्टर- 1, वरदान खण्ड, निकट- आईसीआईसीआई बैंक, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ - 226010

medishop\_foryou | medishop56@gmail.com

# लोक सभा चुनाव से पहले प्रदेश में नया प्रयोग करने की तैयारी में कांग्रेस

## पार्टी में छह कार्यकारी अध्यक्षों के फार्मूले पर कर रही मंथन

- अभी तक नहीं हो सका है प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव
- जातीय और क्षेत्रीय समीकरण साधने पर भी फोकस

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। विधान सभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद अब कांग्रेस की निगाहें लोक सभा चुनाव पर टिक गयी हैं। चुनाव से पहले कांग्रेस एक बार फिर प्रदेश में नया सियासी प्रयोग करने की तैयारी कर रही है। वह पार्टी में छह कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति के फार्मूले को लागू करने पर मंथन कर रही है। हालांकि पार्टी अभी तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव तक नहीं कर सकी है।

प्रदेश में नाजुक दौर से गुजर रही कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने वोट बैंक को साधने की है। विधान सभा चुनाव के बाद कांग्रेस लोक सभा चुनाव पर फोकस कर रही है। लिहाजा वह संगठन को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष के साथ छह कार्यकारी अध्यक्षों की तैनाती के जरिये पार्टी विभिन्न जातियों और क्षेत्रीय समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। किसी जाति विशेष के वरिष्ठ नेता को



### अन्य राज्यों में कर चुकी है नियुक्ति

कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति का प्रयोग कांग्रेस पार्टी अन्य राज्यों में भी कर चुकी है। हरियाणा, पंजाब, बिहार, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और उड़ीसा जैसे राज्यों में पार्टी की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किये गए हैं। वर्ष 2012 में जब निर्मल खत्री प्रदेश अध्यक्ष बनाये गए थे तो उनके साथ आठ जूनल अध्यक्ष नियुक्त किये गए थे। हालांकि कुछ महीने बाद यह व्यवस्था भंग कर दी गई थी।

प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ अन्य जातियों/धर्मों से ताल्लुक रखने वाले पुराने कार्यकर्ताओं को कार्यकारी अध्यक्ष के पदों

पर समायोजित कर वह समाज के एक बड़े हिस्से से खुद को जोड़ने और विभिन्न वर्गों को साथ लेकर चलने का संदेश भी

देना चाहती है। पार्टी ने उम्र में संगठन के पर्यवेक्षण का काम छह राष्ट्रीय सचिवों को सौंप रखा है। इसी आधार पर प्रदेश को छह जोन में बांटकर प्रत्येक की कमान कार्यकारी अध्यक्ष को सौंपने की हिमायत की जा रही है। इसके पीछे एक और तर्क यह भी दिया जा रहा है कि इससे नतीजे देने में सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष की ही नहीं कार्यकारी अध्यक्षों की भी जवाबदेही तय होगी। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता यह कहकर बच नहीं सकेगे कि उन्हें काम करने या नतीजे देने का मौका ही नहीं मिला।

### यूपी में कांग्रेस को मिली महज दो सीटें

उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में पार्टी को सिर्फ दो सीटों पर जीत मिल सकी। यूपी विधान सभा चुनावों के इतिहास में कांग्रेस का यह सबसे खराब प्रदर्शन है। इस विधान सभा चुनाव के लिए प्रदेश में खुद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा मैदान में उतरीं थी लेकिन उन्हें जैसे प्रदर्शन की उम्मीद थी, वैसा नहीं हो सका। कांग्रेस की ओर से सिर्फ अराधना मिश्रा मोना रामपुर खास और महाराजगंज के फरेंदा से वीरेंद्र चौधरी को ही जीत मिल सकी। इसके पहले, 2017 के विधान सभा चुनाव में पार्टी को सात सीटों से संतोष करना पड़ा था। पिछला चुनाव कांग्रेस और सपा ने मिलकर लड़ा था, लेकिन पार्टी कोई कमाल नहीं दिखा सकी थी।

# सीएम योगी की राह पर धामी, उत्तराखंड में भी गरज रहा है बुलडोजर

पूर्व सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुलडोजर एक्शन पर उठाए सवाल

- अंकिता हत्याकांड के बाद बुलडोजर की कार्रवाई फिर सवालों के घेरे में

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीएम योगी की राह पर चल रहे हैं। वहीं अंकिता हत्याकांड के बाद एक बार फिर बुलडोजर की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। यूपी से लेकर उत्तराखंड तक भाजपा का बुलडोजर गरज रहा है मगर अब बुलडोजर एक्शन पर भाजपा के ही लोगों ने सवाल उठाए हैं, वो भी पूर्व सीएम रावत ने इसे गलत ठहराया है। वहीं अंकिता हत्याकांड के पूरे मामले में धामी सरकार ने चुपचाप साध रखी है। धामी सरकार का कहना है कि इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा बल्कि कड़ी कार्रवाई होगी।

अब सवाल यह है कि वनंतरा रिजॉर्ट पर बुलडोजर एक्शन क्या सही निर्णय था? इस सवाल के जवाब में पूर्व सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि जिला प्रशासन कह रहा है कि हमसे कोई अनुमति नहीं ली गई थी। ऐसे में अब यह जांच का विषय बन गया है कि रिजॉर्ट पर किसने कहने पर बुलडोजर चलाया गया। इतनी भी क्या जल्दी थी कि रातोंरात ही रिजॉर्ट पर बुलडोजर एक्शन हुआ। इससे पहले भी बुलडोजर एक्शन पर कई बार सवाल उठाए गए हैं। रावत का कहना है



### बुलडोजर बना बीजेपी शासित राज्यों की पहचान

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल भी अब बीजेपी शासित राज्यों की पहचान बन गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर इन दिनों सीएम योगी का प्रभाव कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। योगी की तरह धामी भी अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति लागू कर चुके हैं। रिसेप्टिविस्ट अंकिता भंडारी के हत्याकांड में सीएम धामी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी के आदेश पर अब मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के आलीशान रिजॉर्ट पर बुलडोजर चल गया। करोड़ों रुपये में बना भव्य रिजॉर्ट पुलिस ने तोड़ दिया।

कि रिजॉर्ट के नियम हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनका पालन नहीं हो पा रहा है जबकि

प्राधिकरण और जिलों के पास फुल अथॉरिटी है। रावत का कहना है कि

### धामी सरकार का रिजॉर्ट और होटलों पर एक्शन

सीएम पुष्कर सिंह की सख्ती के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने अवैध तरीके से बने होटल, रिजॉर्ट और कैफे संचालकों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। एमडीडीए ने एक रिजॉर्ट और तीन कैफे सील किए। सीलिंग की कार्रवाई से संचालकों में हड़कप की स्थिति रही। एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि बिना नक्शा पास कराए या स्वीकृत नक्शे का उल्लंघन कर बने निर्माणों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। राजपुर रोड पर मैजिस्टिक इन में बिना स्वीकृति के कॉफी शॉप का निर्माण और संचालन किया जा रहा था। इस अनाधिकृत

व्यवस्थाओं का अनुपालन जरूरी है। पूर्व सीएम त्रिवेन्द्र ने कहा कि अंकिता हत्याकांड बहुत दुखद है और उत्तराखंड सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। वहीं अंकिता हत्याकांड में धामी सरकार के आदेश के बाद गठित एसआईटी का दावा है कि बुलडोजर एक्शन से पहले सभी जरूरी साक्ष्य जुटा लिए गए थे। एसआईटी टीम द्वारा घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया गया है। अंकिता की

निर्माण को सील कर दिया गया। राजपुर रोड पर ही दिव्या अग्रवाल ने 10 गुणा 10 फीट में पांच हटों (3 पाइन कैफे) का निर्माण बिना स्वीकृति के किया है, जिनको सील कर दिया गया। द स्मोक हाउस में लगभग 14 गुणा 40 फीट क्षेत्रफल में अवैध रूप से टीन शेड का निर्माण कर व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा था, इसे भी सील कर दिया गया। एमडीडीए सचिव ने बताया कि जो अवैध निर्माण कंपाउंडिंग के दायरे में नहीं आएं, उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। एमडीडीए उपाध्यक्ष सोनिका ने बताया कि सभी प्रकार के अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट एम्स से प्राप्त करके परिजनों को दिखाई गई। घटनास्थल से भौतिक साक्ष्यों के साथ-साथ सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सीडीआर आदि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य प्राप्त करके गहनता से विश्लेषण कर अध्ययन किया जा रहा है। प्रकरण के मुख्य गवाहों, रिजॉर्ट कार्मिकों से पूछताछ जारी है। हत्यारोपियों से साक्ष्य प्राप्त करने हेतु पुलिस कस्टडी रिमांड प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।



Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma

@Editor\_Sanjay

जिद... सच की

## सवालियों के घरे में स्वच्छ गंगा मिशन

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन सवालियों के घरे में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए बेहद तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने मिशन के काम को आंखों में धूल झाँकने वाला करार दिया है। साथ ही कहा कि यह केवल पैसा बांटने की मशीन बनकर रह गया है। गंगा की सफाई हो रही है या नहीं इसकी न तो निगरानी की जा रही है न जमीनी स्तर पर ही कोई काम दिख रहा है। टिप्पणी से साफ है कि गंगा की सफाई के नाम पर जमकर गोलमाल हो रहा है। सवाल यह है कि हर साल करोड़ों रुपये पानी की तरह बहाने के बाद भी गंगा मैली क्यों है? लापरवाही के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? आखिर मिशन के नाम पर आर्बिट्ररी धन कहाँ जा रहा है? क्या भ्रष्टाचार ने पूरी मिशन को अपनी चपेट में ले लिया है? केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या कर रहे हैं? सीवर के जरिए गंगा में गंदे पानी का गिरना रोका क्यों नहीं जा सका है? मानक के मुताबिक एसटीपी काम क्यों नहीं कर रहे हैं? गंगा सफाई की निगरानी क्यों नहीं की जा रही है? हाईकोर्ट के सवालियों का जवाब संबंधित विभाग क्यों नहीं दे नहीं पा रहे हैं?

गंगा को निर्मल और अविचल बनाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन का गठन किया गया था। इसके लिए केंद्र सरकार हर साल भारी भरकम बजट जारी करती है। योजना की शुरुआत से अब तक अरबों रुपये गंगा की सफाई के नाम पर खर्च किए जा चुके हैं लेकिन बीएचयू और कानपुर आईटी की रिपोर्ट से साफ है कि गंगा की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा है। वह आज भी मैली है। नदी का प्रदूषण स्तर बढ़ता जा रहा है। पूरे मिशन में घोर लापरवाही बरती जा रही है और योजना के लिए आर्बिट्ररी धन का दुरुपयोग हो रहा है। मिशन के तहत सीवर का पानी सीधे गंगा में गिरने से रोकने के लिए एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) लगाए जाने थे लेकिन यह काम आज तक पूरा नहीं हुआ। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज सहित अन्य शहरों में लगाए गए एसटीपी मानक के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट के सामने केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने भी इसकी पुष्टि की है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े मिशन के कार्यों की निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं है। यह हाल तब है जब तमाम विभागों को इस पूरे मिशन को समन्वित तरीके से संचालित करने की जिम्मेदारी दी गयी है। साफ है मिशन अपने लक्ष्य से कोसों दूर है। यदि सरकार गंगा को निर्मल और अविचल देखना चाहती है तो उसे खुद इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच-पड़ताल करनी होगी और इसकी खामियों को दूर करना होगा। साथ ही धन का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करनी होगी।

Sanjay

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

## संचार क्रांति के खतरे

कृष्ण प्रताप सिंह

हम इक्कीसवीं शताब्दी के 22वें साल के उत्तरार्ध में आ पहुंचे हैं लेकिन अभी भी कुछ ठिकाना नहीं है कि अपनी बच्चियों, किशोरियों और युवतियों की निजता से जुड़े मामलों को लेकर सहज होना और किसी विवाद की स्थिति में उनकी गरिमा की रक्षा करते हुए उसे निपटाने का सामाजिक विवेक कब विकसित कर पायेंगे? ठिकाना होता तो मोहाली के एक विश्वविद्यालय के गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा द्वारा कथित रूप से अन्य छात्रों के आपत्तिजनक वीडियो लीक करने को लेकर जैसा हड़कंप मचा और कई क्षेत्रों में उसे लेकर जैसा ओछापन प्रदर्शित किया गया, उसकी नौबत नहीं आती। तब हम संचार क्रांति के लाभों को हानियों में बदलते देखने को अभिशप्त नहीं होते। साफ कहें तो तब न सोशल मीडिया इतना असामाजिक व असंवेदनशील होता और न कई लोगों को इस निष्कर्ष तक पहुंचने की सहूलियत होती कि हमारे जैसे बन्द समाजों के पुराने नैतिक बंधन अचानक खोल दिये जाएं तो जो निरंकुश खुलापन आता है, वह विवेक से ज्यादा अविवेक का ही सशक्तीकरण करता है। साथ ही कई तरह की कुंठाएं खुलकर कुटिलता से भरे असामाजिक खेल खेलने लगती हैं।

बहरहाल, इस मुद्दे पर जो हंगामा हुआ है, उसकी शुरुआत बिना जांच-पड़ताल के प्रसारित इस 'सनसनीखेज' खबर से हुई कि एक छात्रा ने कई अन्य छात्रों के नहाते वक्त उनके वीडियो बनाकर अपने व्हाट्सएप फ्रेंड को भेज दिये, जिसने उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। सोशल मीडिया पर कोई भी बात जंगल की आग से भी तेज गति से फैल जाती है और फैलाने वालों के नियंत्रण से भी बाहर हो जाती है। ऐसा लगता है कि फेंके हुए ढेले के हाथ न आने की हमारे पुरखों की कहावत इस मीडिया के संदर्भ में ही सबसे ज्यादा सार्थक है। ऐसे में अभी कहना मुश्किल है कि इस मामले का सच क्या है और

उसे लेकर फैलाये जा रहे झूठ या अर्धसत्य कब, कहाँ और कैसे थमेंगे। हमारे समाज में इस तरह के मामलों को जिस तरह चटखारे के साथ सुना व सुनाया या देखा और दिखाया जाता है, साथ ही उसमें अपनी ओर से कुछ जोड़कर बताया जाता है, उसके कारण यह और भी मुश्किल है। यह मामला सनसनीखेज नहीं, गंभीर साइबर अपराध है और उससे साइबर अपराध की ही तरह निपटा जाना चाहिए। ऐसे अपराधों की चपेट में अब सामान्य लोग भी आ रहे हैं। कारण यह कि देश में साइबर अपराधियों को अपने नापाक इरादे पूरे करने के लिए संचार तकनीक के किसी भी तरह के दुरुपयोग से डर

बिजली के करंट की चपेट में आ जाते हैं तो हम यह मांग नहीं करते लगते कि उन्हें बिजलीचालित उपकरणों का इस्तेमाल न करने दिया जाये लेकिन आश्चर्य नहीं कि युवतियों की अपनी मर्जी से जीवन जीने के अधिकार के विरोधी इस कथित एमएमएस लीक की आड़ में उन पर बंदिशों की वकालत करने और उनके आगे पढ़ने की राह में बाधाएं डालने के प्रयास करने लगे इसलिए जितना जरूरी साइबर अपराधियों के मंसूबों को विफल करना है, उतना ही इन तत्वों के मंसूबों को विफल करना भी।

किसी भी आरोपी को विलेन बनाने से पहले निष्पक्ष जांच की जानी



नहीं लगता क्योंकि सरकार अभी उनसे निपटने के लिए उपयुक्त कानून ही नहीं बना पाई है।

देश में जब से सूचना क्रांति आई और मोबाइल व इंटरनेट के रास्ते सूचनाओं की पहुंच तीव्र हुई तभी से यह बहस का मुद्दा बना है कि क्या मोबाइल व इंटरनेट पारंपरिक समाजों में बच्चों, किशोरों व छात्रों से छिपाकर रखी जाने वाली तमाम बातें बताकर उन्हें बिगाड़ रहे हैं लेकिन साइबर अपराध कैसे रोके जायें या उनसे जुड़े अपराधियों को माकूल सजा कैसे अमल पाये, इस पर अपवादस्वरूप ही चर्चा होती है।

वहीं पितृसत्ताजनित सोच के पैरोकार संगठन युवतियों व महिलाओं को मोबाइल से दूर रखने में ही समस्या का एकमुश्त समाधान देखते हैं, जिसे इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता कि असावधानी बरतने वाले लोग

चाहिए कि उसके पीछे छुपा 'सूत्रधार' कौन था? क्या उसने किसी के दबाव में ऐसा किया? क्या उसके पीछे कोई बड़ा गिरोह है? 18 साल पहले दिल्ली के एक नामी स्कूल में ऐसा ही कांड हुआ था तो पीड़िता के माता-पिता ने उसे विदेश भेज दिया था। लेकिन सारे माता-पिता इतने सक्षम नहीं होते और यह कोई समाधान भी नहीं है इसलिए बच्चियों को ऐसे साइबर अपराधों से बचाने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि खुलेपन की हवा में सांस लेने लगा हमारा समाज अब अपनी बंद मानसिकता से छुटकारा पाकर नयी पीढ़ी में आ रहे बदलावों को समझने की कोशिश करे। पिछले 20-25 सालों में दुनिया में बहुत तेजी से चीजें बदली हैं। नयी पीढ़ी ने उन बदलावों को जिया और आत्मसात किया है, लेकिन उससे पुरानी पीढ़ी उनको लेकर सहज नहीं हो पाई है।

पंकज चतुर्वेदी

इस बार बरसात में बस दिल्ली बची थी। चेन्नई, हैदराबाद, बंगलुरु, लखनऊ, भोपाल, पटना, रांची आदि मानसून की तनिक-सी बौछार में डूब चुके थे। विदा होते मानसून में निचले स्तर पर चक्रवाती स्थिति क्या बनी, बादल जम कर बरसे और फिर विज्ञापनों में यूरोप-अमेरिका को मात देते दिल्ली के विकास के दावे पानी-पानी हो गये। अत्याधुनिक वास्तुकला के उदाहरण प्रगति मैदान की सुरंग में वाहन फंसे रहे तो तेज रफ्तार ट्रैफिक के लिए खंभों पर खड़े बारापुला पर वाहन थम गये। एम्स के बहुमार्गी पुल तो स्विमिंग पूल बन गये। कम्प्लेक्स यही स्थिति उन सभी नगरों की है, जिन्हें हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं। दुर्भाग्य है कि शहरों में अब बरसात आनंद ले कर नहीं आती। दुर्भाग्य है कि शहरों में हर ईंसान किसी तरह भरे हुए पानी से बच कर अपने मुकाम पर पहुंचना चाहता है लेकिन वह सवाल नहीं करता कि आखिर ऐसा क्यों व कब तक?

यह तो अब गोरखपुर, बलिया, जबलपुर या बिलासपुर जैसे मध्यम शहरों की भी त्रासदी हो गयी है कि थोड़ी-सी बरसात हो या आंधी चले तो सारी मूलभूत सुविधाएं जमीन पर आ जाती हैं। जब दिल्ली सरकार हाईकोर्ट के आदेशों की परवाह नहीं करती और हाईकोर्ट भी अपनी नाफरमानी पर मौन रहता है, तो जाहिर है कि आम आदमी क्यों आवाज उठायेगा? दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 अगस्त, 2012 को जल जमाव का स्थायी निदान खोजने के आदेश दिये थे। दक्षिणी दिल्ली में 31 अगस्त, 2016 को जल जमाव से सड़कें जाम होने पर दायर एक याचिका पर कोर्ट ने कहा था कि जल जमाव की अनदेखी नहीं की जा सकती। दिल्ली हाईकोर्ट की एक बेंच ने 15

## ऐसे शहर तो डूबेंगे ही



जब दिल्ली सरकार हाईकोर्ट के आदेशों की परवाह नहीं करती और हाईकोर्ट भी अपनी नाफरमानी पर मौन रहता है तो जाहिर है कि आम आदमी क्यों आवाज उठायेगा? दिल्ली हाईकोर्ट ने 22 अगस्त, 2012 को जल जमाव का स्थायी निदान खोजने के आदेश दिये थे। दक्षिणी दिल्ली में 31 अगस्त, 2016 को जल जमाव से सड़कें जाम होने पर दायर एक याचिका पर कोर्ट ने कहा था कि जल जमाव की अनदेखी नहीं की जा सकती।

जुलाई, 2019 को दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि जल जमाव व यातायात बाधित होने की त्वरित निगरानी व निराकरण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो। अदालत ने 31 अगस्त, 2020 को जल जमाव का समाधान खोजने का निर्देश दिया था। कई अन्य राज्यों से भी इस तरह के आदेश हैं।

इस समस्या का कारण महज जल जमाव वाले स्थान पर बनी निकासी की कभी सफाई नहीं होना व उसमें कूड़ा गहरे तक जमा होना ही था। इस कार्य के लिए हर महीने हजारों वेतन वाले कर्मचारी व उनके सुपरवाइजर तैनात हैं। विडंबना है कि शहर नियोजन के लिए गठित सरकारी अमले पानी के बहाव में शहरों के ठहरने पर खुद को असहाय पाते हैं। सारा दोष नालों की सफाई न होने,

बढ़ती आबादी, घटते संसाधनों और पर्यावरण से छेड़छाड़ पर थोप देते हैं। इसका जवाब कोई नहीं दे पाता है कि नालों की सफाई सालभर क्यों नहीं होती और इसके लिए मई-जून का इंतजार क्यों होता है? इसके हल के सपने, नेताओं के वादे और पीड़ित जनता की जिंदगी नये सिरे से शुरू करने की हड़बड़ाहट सब कुछ भुला देती है। यह सभी जानते हैं कि दिल्ली में बने ढेर सारे पुलों के निचले सिरे, अंडरपास और सब-वे हल्की बरसात में जलभराव के स्थायी स्थल हैं लेकिन कोई यह जानने का प्रयास नहीं कर रहा है कि आखिर निर्माण की डिजाइन में कोई कमी है या फिर उसके रखरखाव में?

अचानक तेजी से बहुत बरसात हो जाना एक प्राकृतिक आपदा है और जलवायु परिवर्तन की मार के

दौर में यह स्वाभाविक भी है, लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए मूलभूत कारण पर सभी आंख मूंदे रहते हैं। दिल्ली, कोलकाता, पटना जैसे महानगरों में बरसात का जल गंगा-जमुना तक जाने के रास्ते छेक दिये गये। मुंबई में मीठी नदी के उथले होने और सीवर की 50 साल पुरानी सीवर व्यवस्था के जर्जर होने के कारण बाढ़ के हालात बनना सरकारें स्वीकार करती रही हैं। बंगलुरु में पारंपरिक तालाबों के मूल स्वरूप में अवांछित छेड़छाड़ को बाढ़ का कारक माना जाता है। दिल्ली में सैकड़ों तालाब व यमुना नदी तक पानी जाने के रास्ते पर खेल गांव से लेकर ओखला तक बसा दिये गये। शहरों में बाढ़ रोकने के लिए सबसे पहला काम तो वहां के पारंपरिक जल स्रोतों में पानी की आवक और निकासी के पुराने रास्तों में बने निर्माणों को हटाने का करना होगा। यदि किसी पहाड़ी से पानी नीचे बह कर आ रहा है, तो उस पानी का संग्रह किसी तालाब में ही होगा। विडंबना है कि ऐसे जोहड़-तालाब कंक्रीट की नदियों में खो गये हैं।

महानगरों में भूमिगत सीवर जल भराव का सबसे बड़ा कारण है। जब हम भूमिगत सीवर के लायक संस्कार नहीं सीख पा रहे हैं तो फिर खुले नालों से अपना काम क्यों नहीं चला पा रहे हैं? पॉलीथीन, घर से निकलने वाले रसायन और नष्ट न होने वाले कचरे की बढ़ती मात्रा, कुछ ऐसे कारण हैं जो गहरे सीवरों के दुश्मन हैं। सीवरों और नालों की सफाई भ्रष्टाचार का बड़ा माध्यम है। महानगरों में बाढ़ का मतलब है परिवहन और आवागमन का ठप होना। इससे ईंधन की बर्बादी, प्रदूषण में वृद्धि और मानवीय स्वभाव में उग्रता जैसे कई दुष्परिणाम होते हैं। जल भराव और बाढ़ मानवजन्य समस्याएं हैं और इसका निदान दूरगामी योजनाओं से ही संभव है।



**स**लमान खान का कन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस का सीजन 16 जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाला है। यह शो 1 अक्टूबर से टेलीकास्ट होगा, जिसमें इस बार बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। बिग बॉस 16 के अब तक जितने भी प्रोमो वीडियो सामने आए हैं, उनमें कहा गया है कि इस बार बिग बॉस खुद खेल खेलेंगे, जिस वजह से बीबी हाउस के फैंस शो के लिए एक्साइट्रेड हैं। इतना ही नहीं, बिग बॉस 16 में आने वाले किसी भी कंटेस्टेंट का नाम अब तक रिवील नहीं किया गया है। लेकिन इन सबके बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें नए कंटेस्टेंट की झलक दिखाई गई है। कलर चैनल ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर बिग बॉस 16 का नया प्रोमो शेयर किया है, जिसमें नए कंटेस्टेंट की जानकारी दी गई है। इस वीडियो में देखा जा

# बिग बॉस में सलमान से पंगा लेंगी निम्रत कौर



सलमान खान की एक एक्ट्रेस नजर आ रही है, जो खुद को देश की पॉपुलर बहू बता रही है। यानी बिग बॉस के

सीजन 16 में भी बहू के रूप में मशहूर एक एक्ट्रेस आने वाली हैं। वीडियो में बिग बॉस कहते हैं, सुना है आप कभी कोई बहस नहीं हारतीं। इस पर वह कहती हैं, हिन्दुस्तान की चहेती बहू होने के साथ

में एक लॉयर भी हूँ। इस कॉम्बिनेशन के साथ कैसे हार सकती हूँ। इस बार भी बिग बॉस के मेकर्स ने शो की कंटेस्टेंट का नाम और चेहरा छिपाने की कोशिश की है लेकिन वीडियो में दिखी हल्की सी झलक और आवाज से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह अभिनेत्री निम्रत कौर हैं, जो टीवी सीरियल छोटी सरदारनी में नजर आई हैं। इस शो में अभिनेत्री ने मेहर का किरदार निभाया है।

बॉलीवुड

मसाला

## बॉलीवुड मन की बात

### ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में ऋतिक रोशन की एंट्री



बॉ

लीवुड एक्टर ऋतिक रोशन ने हाल ही में खुलासा किया कि वो अयान मुखर्जी की ब्लॉकबस्टर फिल्म ब्रह्मास्त्र पार्ट वन शिवा के सीक्वल में दिखाई दे सकते हैं। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान ऋतिक से ब्रह्मास्त्र के दूसरे पार्ट में काम करने की खबरों के बारे में पूछा गया तो इसके जवाब में उन्होंने कुछ ऐसा कहा, जिससे सबको कंफर्म हो गया कि वो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में नजर आएंगे। पीटीआई से बातचीत के दौरान ऋतिक से ब्रह्मास्त्र के साथ-साथ नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में उनको कास्ट किए जाने को लेकर भी सवाल किया गया। इस पर रिप्लाइ करते हुए ऋतिक ने कहा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मेरी अगली फिल्म फाइटर है। इसके बाद इन सभी प्रोजेक्ट्स से जुड़ने की संभावना है, जिनके बारे में आप बात कर रहे हो। फिंगर्स क्रॉस। आपको बता दें ब्रह्मास्त्र का दूसरा पार्ट देव पर बनने वाला है। ब्रह्मास्त्र की रिलीज के बाद फैंस कयास लगा रहे थे कि ऋतिक इस फिल्म के दूसरे पार्ट में देव की भूमिका निभाएंगे। हालांकि उन्हें फिल्म के पहले पार्ट में नहीं देखा गया है। इस फिल्म के दूसरे पार्ट के लिए ऋतिक के अलावा रणवीर सिंह और कार्तिक आर्यन के नाम का भी फैंस अनुमान लगा रहे थे। अब ऋतिक ने कुछ कन्फर्म तो नहीं किया, लेकिन उनके इस बयान से फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि शायद वो ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में नजर आएंगे। ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को भारत की 5,019 स्क्रीन्स और ओवरसीज में करीब 3,894 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने अब तक 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। ब्रह्मास्त्र की रिलीज से सिनेमाघरों में वापस जान आ गई है। ये फिल्म ऑडियंस को थिएटर लाने में कामयाब रही, जो कि हालिया रिलीज बॉलीवुड फिल्में नहीं कर पाई थीं। इस फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है।



## अयोध्या में होगा आदिपुरुष का टीजर लॉन्च

**स**उथ सुपरस्टार प्रभास, कृति सेनन और सैफ अली खान स्टारर फिल्म आदिपुरुष साल 2023 की मच अग्रेड फिल्मों में से एक है। लंबे समय से फैंस इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में खबरें आ रही थी कि आदिपुरुष का टीजर प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या में किया जाएगा। अब इस खबर की पुष्टि खुद साउथ के फेमस फिल्म क्रिटिक और इंडस्ट्री ट्रेंडर मनोबाला विजयबालन ने की है। मनोबाला ने अपने

ट्विटर हैंडल पर लिखा- आदिपुरुष फिल्म का भव्य टीजर लॉन्च 2 अक्टूबर को अयोध्या में कंफर्म किया गया है। फिल्म आदिपुरुष में प्रभास प्रभु श्री राम से प्रेरित भूमिका निभाने वाले हैं। ऐसे में मेकर्स ने टीजर लॉन्च के लिए नवरात्र का समय चुना है। पहले खबरें थी आदिपुरुष का टीजर 3 अक्टूबर को लॉन्च होगा, लेकिन अब मेकर्स ने 2 अक्टूबर की टीजर लॉन्च डेट कंफर्म की है। खबरें हैं कि आदिपुरुष के मेकर्स फिल्म का ग्रैंड लॉन्च प्लान कर रहे हैं, इसलिए पूरी टीम और स्टारकास्ट 2 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेगी। आदिपुरुष प्रोडक्शन

टीम ने नवंबर 2021 में ही फिल्म की शूटिंग कंफ्लिट कर ली थी। लेकिन फिल्म का फोकस विजुअल इफेक्ट्स पर था, जिस वजह से मेकर्स को फिल्म तैयार करने में लंबा समय लग गया। पहले फिल्म को 2022 में रिलीज किया जाना था, लेकिन अब आदिपुरुष के 12 जनवरी 2023 को रिलीज किया जाएगा। आदिपुरुष का बजट प्रभास की फिल्म बाहुबली से भी ज्यादा है, ऐसे में मेकर्स को इस फिल्म से काफी उम्मीदें हैं। इस फिल्म को टी-सीरीज बैनर के तले तैयार किया गया है, वहीं फिल्म को थ्री-डी में रिलीज किया जाएगा।

## ये है दुनिया का सबसे बड़ा फूल, बिना नाक बंद किए जिसे देखना है नामुमकिन

दुनियाभर में सैकड़ों तरह के पेड़-पौधे और उनके फूल पाए जाते हैं। कई फूल बहुत खूबसूरत और अच्छी सुगंध वाले होते हैं लेकिन आज हम आपको एक ऐसे फूल के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा, क्योंकि ये फूल दुनिया का सबसे बड़ा फूल माना जाता है, लेकिन इसे देखने के लिए आपको सबसे पहले अपनी नाक बंद करनी पड़ेगी। नाक बंद करने की बात जानकर यकीनन आप हैरान होंगे लेकिन बात बिल्कुल सही है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े फूल को देखने के लिए आपको अपनी नाक बंद करनी पड़ेगी। दरअसल, हम बात कर रहे हैं एमोर्फोफेलस टायटेनम नाम के एक फूल के बारे में, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फूल लोगों को अपनी और आकर्षित तो करता है मगर कोई भी इसके करीब जाने के लिए दस बार जरूर सोचता है। 'एमोर्फोफेलस टायटेनम' नाम का यह फूल ज्यादातर इंडोनेशिया के सुमात्रा इलाके में पाया जाता है। जो अपनी 40 साल की आयु में ये सिर्फ चार बार ही खिलता है। यही नहीं ये सिर्फ 48 घंटे यानी सिर्फ दो दिनों के लिए ही खिलता है और उसके बाद मुरझा जाता है, खिलने पर इसकी ऊंचाई लगभग तीन मीटर तक होती है, जो किसी इंसान की ऊंचाई से भी ज्यादा है। इस प्रजाति के फूल के सुखियों में आने के बाद दुनिया के कई देशों ने इसे अपने अपने देशों में जगह दी है और इसके खिलने पर उस जगह लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े फूल का दर्ज प्राप्त इस फूल से ऐसी खुशबू नहीं आती कि लोग इसके पास न चाहते हुए भी पहुंच जाएं, बल्कि इस फूल से ऐसी दुर्गंध आती है जैसे सड़े हुए मांस से आती हो। इसीलिए इसे देखने के लिए लोगों को पहले अपनी नाक बंद करनी पड़ती है। इसलिए इस फूल को दुनिया के सबसे बड़बूदार फूल के रूप में भी जाना जाता है। पिछली बार यह फूल जापान के टोक्यो स्थित जिंई बोटैनिकल गार्डन में खिला था। टायटेनम की इस प्रजाति को दुनिया की सबसे संवेदनशील प्रजाति की सूची में शामिल किया गया है।

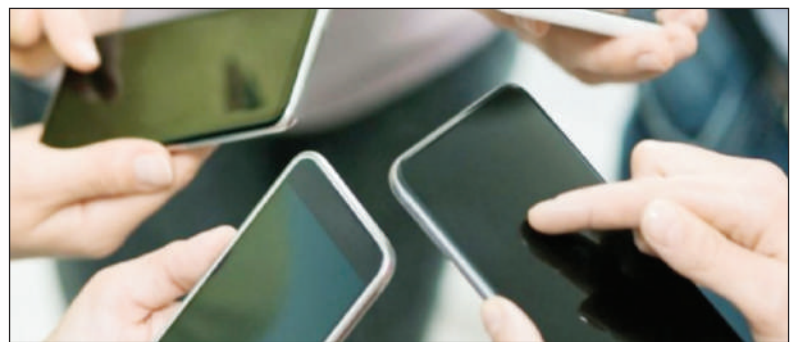


## अजब-गजब

सरपंच ने डिजिटल दुनिया के कुप्रभाव से बचने को निकाला अनोखा तरीका

### मंदिर से सायरन बजते ही बंद हो जाते हैं टीवी, मोबाइल फोन

टेक्नोलॉजी के इस दौर में मोबाइल और इंटरनेट ने लोगों की जिंदगी बदल दी है। मोबाइल और इंटरनेट के जरिए लोगों के बहुत से काम आसान हो जाते हैं। हालांकि अब लोगों को इनकी लत लग गई है। लोग अब मोबाइल, टीवी जैसे गैजेट्स पर ज्यादा समय बिताते हैं। इससे वे अपने परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों से दूर होते जा रहे हैं। वहीं कई रिसर्च में भी इस बात का खुलासा हो चुका है कि मोबाइल जैसे गैजेट्स पर घंटों समय बिताने से इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं और यह आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में सांगली के एक गांव में डिजिटल दुनिया के गलत प्रभाव से बचने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। यहां रोजाना डेढ़ घंटे के लिए लोग अपने मोबाइल, टीवी और दूसरे गैजेट्स को बंद कर देते हैं। इसके लिए बाकायदा मंदिर से सायरन बजाया जाता है।



समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इस अनोखी पहल का प्रस्ताव गांव के सरपंच विजय मोहिते ने रखा। अब लोग उनकी मुहीम से जुड़ रहे हैं। रोजाना शाम को 7 बजे गांव के मंदिर से सायरन बजाया जाता है। सायरन बजते ही गांव के लोग मोबाइल, टेलीविजन और दूसरे गैजेट्स को बंद कर लेते हैं। इस दौरान लोग किताबें पढ़ते हैं और बच्चे अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। कई लोग साथ में बैठकर एक दूसरे से बातें करते हैं। करीब डेढ़ घंटे तक यहां लोग अपने गैजेट्स बंद रखते हैं। इसके

बाद रात 8:30 बजे दूसरा अलार्म बजता है। इसके बाद लोग फिर से अपने मोबाइल और टीवी को स्वीच ऑन कर लेते हैं। गांव के सरपंच ने पीटीआई से बात करते हुए बताया कि कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन क्लास की वजह से बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन आ गए। वहीं माता-पिता ज्यादा देर तक टीवी देखने लगे। अब जब सब ठीक हो गया और फिजिकल क्लास शुरू हो गई तो टीचर्स को लगा कि बच्चे आलसी हो गए हैं, वो पढ़ना-लिखना नहीं चाहते थे। इसके अलावा ज्यादातर बच्चे स्कूल के समय से पहले और बाद में अपने मोबाइल फोन में तल्लीन रहते थे। ऐसे में गांव के सरपंच को डिजिटल डिटॉक्स का विचार आया जो उन्होंने लोगों के सामने रखा। शाम 7 बजे से 8.30 बजे के बीच

अपने मोबाइल फोन एक तरफ रखते हैं, टेलीविजन सेट बंद कर देते हैं और पढ़ने-लिखने और बातचीत पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गांव के लोग इसे फॉलो कर रहे हैं या नहीं इस बात की निगरानी के लिए एक वार्ड समिति का गठन किया गया है। यह समिति नजर रखती है कि लोग इसका पालन कर रहे हैं या नहीं। साथ ही सरपंच ने बताया कि शुरू में इस पहल को लेकर लोगों में हिचकिचाहट थी क्या मोबाइल और टीवी स्क्रीन से दूर रहना संभव है। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस पर, महिलाओं की एक ग्राम सभा बुलाई और एक सायरन खरीदने का फैसला किया। इसके बाद आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, ग्राम पंचायत कर्मचारी, सेवानिवृत्त शिक्षक डिजिटल डिटॉक्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए घर-घर गए।

# बिहार में भाजपा को नहीं जीतने देंगे एक भी लोक सभा सीट : तेजस्वी

» महागठबंधन की सरकार बनने के बाद विपक्ष में बौखलाहट

» केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर भी साधा निशाना

» 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

पटना। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली से पटना लौटने के बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक बार फिर भाजपा पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से ही विपक्ष में बौखलाहट है। पिछले बार के लोक सभा चुनाव में 40 में 39 सीटों पर जीत हुई थी लेकिन इस बार एक भी सीट नहीं जीतने देंगे।

उन्होंने कहा कि 2024 के लोक सभा चुनाव में बिहार में क्या होने वाला है, ये जानकर भाजपा बेचैन हैं। सीएम नीतीश कुमार के विपक्षी एकजुटता के प्रयास पर भाजपा

के तंज पर तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के नेताओं के बीच कंपटीशन चल रहा है। सबको अपना काम करना है। तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर भी तंज कसा है। डिप्टी सीएम तेजस्वी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि केंद्रीय मंत्री पूर्णिया एयरपोर्ट का टिकट कटवा लें, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ। गौरतलब है कि अमित

शाह ने बिहार के दो दिवसीय दौरे के दौरान इस बात की जिज्ञासा की थी कि पूर्णिया में एयरपोर्ट बन गया है। इसको लेकर सत्ता पक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर है।

वहीं जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी पटना में जन जागरण अभियान के दौरान भाजपा पर सियासी वार किया। उन्होंने कहा कि 2024 में भाजपा को जनता सबक सिखाएगी। लोक सभा चुनाव में बिहार में भाजपा को लोक सभा की एक भी सीट नहीं मिल पाएगी।



## सपा विधायक नाहिद हसन को चित्रकूट जेल किया गया ट्रांसफर

» 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

मुजफ्फरनगर। कैराना सीट से सपा विधायक नाहिद हसन को जिला कारागार से चित्रकूट जेल भेज दिया गया है। बीते जनवरी माह में उन्हें गैंगस्टर के मामले में जेल भेजा गया था।

नाहिद हसन ने जिला कारागार से ही सपा के टिकट पर कैराना विधान सभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। तब से वह जिला कारागार में बंद थे। सूत्रों की माने तो शासन के आदेश पर मंगलवार को नाहिद हसन को जिला कारागार से चित्रकूट जेल भेजा गया है। देर रात कड़ी सुरक्षा के बीच नाहिद हसन को जिला कारागार से चित्रकूट के लिए रवाना किया गया। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने नाहिद हसन को दूसरी जेल भेजे जाने की पुष्टि की है। नाहिद हसन के मुजफ्फरनगर जिला कारागार से ट्रांसफर करने से पूर्व मंगलवार को दिन में जिला जज, डीएम व एसएसपी जिला कारागार में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। इसके बाद शामली के जिला जज, डीएम और एसपी ने भी जिला कारागार का निरीक्षण किया था।

» गैंगस्टर मामले में जेल में हैं बंद



## सुप्रीम कोर्ट में उद्भव को झटका अब चुनाव आयोग तय करेगा कौन है असली शिवसेना

» आयोग के फैसला करने पर रोक लगाने से इंकार

» 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्भव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट में बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद चुनाव आयोग को एकनाथ शिंदे समूह के असली शिवसेना होने के दावे पर फैसला करने से रोक लगाने से इंकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि उद्भव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच शिवसेना में पार्टी के बीच विवाद का फैसला करने के लिए चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी जिसमें किसका मूल पार्टी पर अधिकार या चुनाव चिन्ह हासिल कर सकेगा। जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा ने उद्भव ठाकरे गुट द्वारा दायर की गई एक याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया कि चुनाव आयोग को



मामले में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जब तक कोर्ट शिवसेना विधायकों की अयोग्यता से संबंधित याचिका का फैसला नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग को हम निर्देश देते हैं कि कार्यवाही पर कोई रोक नहीं होगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सरकार बदलने और पार्टी में बागवत के बाद शिवसेना दो गुटों में बंट गई है। दोनों गुट पार्टी और उसके चुनाव चिन्ह पर अपना दावा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्भव ठाकरे ने खुद के असली शिवसेना होने का दावा किया है।

## राम प्रकाश गुप्ता मदर एंड चाइल्ड रेफरल अस्पताल को ब्लड सेंटर का लाइसेंस

» इंग लाइसेंसिंग एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने जारी किया लाइसेंस

» 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यूपी की इंग लाइसेंसिंग एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने राम प्रकाश गुप्ता मदर एंड चाइल्ड रेफरल अस्पताल को ब्लड सेंटर का लाइसेंस जारी किया है। इसके साथ ही अब अस्पताल रक्त और उसके घटकों को इकट्ठा, उसे स्टोर, संशोधित और वितरित कर सकेगा। इससे मरीजों को राहत मिलेगी।

अस्पताल प्रशासन ने बताया कि अथॉरिटी से रक्त केंद्र का लाइसेंस जारी किया गया है। अब हम सभी रक्त घटक (स्टेम सेल को छोड़कर) उपलब्ध कराएंगे। हम यूपी में एकमात्र केंद्र हैं जहां एक ही संस्थान में दो लाइसेंस प्राप्त रक्त केंद्र हैं। अस्पताल प्रशासन ने संबंधित प्रशासन और संकाय को इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है।



## राजस्थान सरकार अल्पमत में गहलोट दें इस्तीफा : देवनानी

» पूर्व शिक्षा मंत्री ने सीएम गहलोट पर बोला हमला

» 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

अजमेर। पूर्व शिक्षा मंत्री व अजमेर उत्तर के भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ चुकी है और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोट को सरकार चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है इसलिए उन्हें तत्काल अपने पद से इस्तीफा राज्यपाल को सौंप कर विधान सभा भंग करने की सिफारिश करनी चाहिए ताकि राज्य की जनता बेहतर तरीके से अपनी नुमाइंदगी करने वाले राजनीतिक दल को चुन सके।

उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री और कांग्रेस विधायक अपने आलाकमान के सगे नहीं हुए, वे जनता के सगे कभी भी नहीं हो सकते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कांग्रेस में इतना ज्यादा बवाल होने के बाद भी गहलोट का मुख्यमंत्री बने रहना बड़ी हास्यास्पद और अचरज



वाली बात है। जब गहलोट खेमे के 90 विधायक विधान सभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंप चुके हैं, तो वे अब विधायक ही नहीं रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस सरकार पूरी तरह अल्पमत में आ गई है। उन्होंने कहा कि यदि विधान सभा भंग की जाती है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और फिर कुछ समय बाद विधान सभा चुनाव हो जाएंगे तो जनता को अपने हितों की चिंता व रक्षा करने वाली पार्टी भाजपा को चुनने का अवसर मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि अगली भाजपा सरकार निश्चित रूप से जनता की नुमाइंदगी करेगी और सुशासन देगी।

## गहलोट को हटाया तो राजस्थान में सरकार बचाना मुश्किल!

» 4पीएम की परिचर्चा में उठे कई सवाल

» 4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं तो दूसरी तरफ राजस्थान कांग्रेस में मारामारी मची है। सीएम की कुर्सी की लड़ाई एक बार फिर तेज हो गयी है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान में सियासी घमासान के बीच राहुल के भारत जोड़ो यात्रा पर क्या फर्क पड़ेगा? इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े, सुशील दुबे, अजय शुक्ला, सबा नकवी और 4पीएम के संपादक संजय शर्मा ने एक लंबी परिचर्चा की।

सुशील दुबे ने कहा कि दुनिया में दो ही खानदान हैं एक ब्रिटेन का राजशाही खानदान तो दूसरा गांधी खानदान। गांधी खानदान में तीन-तीन पीएम के डीएनए की विरासत लिए हैं।



मगर इस समय किसी पद नहीं लेना चाहते हैं को पप्पू बना दिया गया है। हालांकि यात्रा करके वे बदलाव ला रहे हैं। सबा नकवी ने कहा कि बड़ी पेंचोदा स्थिति है। शायद कांग्रेस को गहलोट के साथ समझौता करना पड़ेगा। खबर यह भी है कि अध्यक्ष गिर जाएंगे। अशोक वानखेड़े ने कहा कि पवन बंसल ने जो पर्चा लिया, वो खुद के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए लिया है। छत्तीसगढ़ में बधेल अध्यक्ष थे मगर एक नक्सली हमले में

कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। एमपी में तीन दावेदार थे, ज्योतिरादित्य बीजेपी में चले गए। राजस्थान में गहलोट ताकतवर नेता है, बड़ा नाम है। किसने कहा सचिन को मुख्यमंत्री बना देंगे। राहुल ने खुद कहा कि स्पीकर तय करें कि दोनों में से मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अजय शुक्ला ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नैतिक यात्रा है। मुद्दों की यात्रा हैं इसलिए वैसी ही चलेगी। उन्होंने कहा कि ये नाटक नहीं ये नैतिकता है, मापदंड है। राहुल गांधी के अलावा कोई और नहीं कर सकता है। प्रियंका भी नहीं कर सकती। प्रियंका का कमरा सोनिया के बगल में है। राहुल गांधी भी नैतिकता का पालन करते हैं। सचिन पायलट से मेरी बात हुई, उन्होंने खुद कहा कि चुनाव में अच्छा किया तो विचार किया जा सकता है।

**HSJ**  
SINCE 1893

harsahaimal shiamlal jewellers

NOW OPNED

PHOENIX  
PALASSIO

DISCOUNT  
COUPON  
UP TO  
20%

ASSURED GIFTS FOR FIRST 300 BUYERS & VISITORS

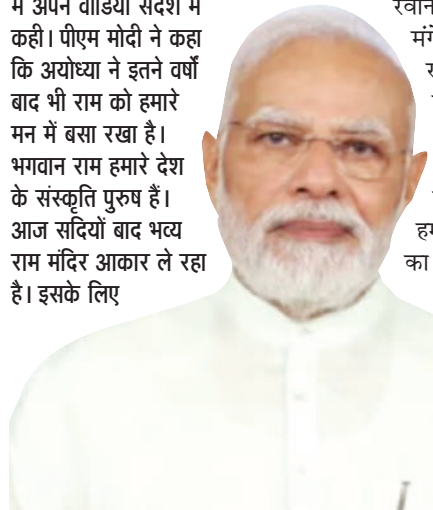
www.hsji.co.in

# अयोध्या में लता चौक का लोकार्पण लता दीदी के स्वरों में गूंजती है पवित्रता : मोदी

» उनके सुर युगों-युगों तक देश के कण-कण को जोड़े रखेंगे

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। लता दीदी के स्वरों में आस्था, आध्यात्मिकता व पवित्रता गूंजती है। उनके गाए हुए भजनों में दैवीय मधुरता थी। उनके स्वर युगों-युगों तक देश के कण-कण को जोड़े रखेंगे। ये बातें प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में लता चौक के लोकार्पण समारोह में अपने वीडियो संदेश में कही। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या ने इतने वर्षों बाद भी राम को हमारे मन में बसा रखा है। भगवान राम हमारे देश के संस्कृति पुरुष हैं। आज सदियों बाद भव्य राम मंदिर आकार ले रहा है। इसके लिए



कोटि-कोटि भक्तों को बधाई और शुभकामनाएं हैं।

वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण किया। इस मौके पर उनके साथ केन्द्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी सहित कई मंत्री व नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीणा निर्माता राम सुतार से भी मुलाकात की। इसके बाद वह रामकथा पार्क के लिए रवाना हो गए। लोकार्पण समारोह में लता मंगेशकर के भतीजे व बहू भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि आज अयोध्या अपना पुराना गौरव प्राप्त कर रही है। रामनगरी को सजाने-संवारने की जिम्मेदारी हम सबकी है। आज हमने लता चौक का लोकार्पण कर दिया है। इसी तरह नगर के हर चौराहे को भव्य बनाया जाएगा। चौक में 92 कमल के फूल लगाए गए हैं जो कि उनके जीवन के वर्षों को दिखाएंगे।

## अयोध्या को तीर्थ केंद्र के रूप में विकसित करेंगे : सीएम योगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या नगर में लता चौक की तरह ही, हर चौक को महर्षि वाल्मीकि, रामानंदचार्य और अलग-अलग महर्षियों के नाम पर बनाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 500 वर्षों के इज्जत के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। इसी तरह हम अपने सभी तीर्थों को सजाएंगे। नगर में एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जा रहा है।



उन्होंने कहा कि हम विकास के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आने देंगे। अयोध्या को तीर्थ केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। अब से रामनगरी का नयाघाट बंधा चौराहा अब लता मंगेशकर चौराहा के नाम से जाना जाएगा। मुख्य कार्यक्रम स्थल रामकथा पार्क में लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। समारोह में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्यगोपाल दास व प्रदेश सरकार के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, सांसद लालू सिंह, नगर विधायक वेदप्रकाश गुप्ता, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय सहित कुछ चुनिंदा संत-धर्मचार्य मौजूद हैं।

## इलाज के लिए लालू यादव को मिली विदेश जाने की अनुमति

□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। दिल्ली की राजज एवेन्यू कोर्ट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव के लिए बुधवार को राहत भरी खबर आई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है। राजज एवेन्यू कोर्ट से बिहार के पूर्व सीएम ने 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इलाज के लिए सिंगापुर जाने की अनुमति मांगी थी। इसके लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।



बुधवार को सुनवाई के बाद राजज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव को विदेश जाने की अनुमति दे दी।

कोर्ट से अनुमति मिलने के अब लालू प्रसाद यादव किडनी संबंधी बीमारी का इलाज कराने के लिए सिंगापुर जा सकेंगे। गौरतलब है कि लालू यादव अपनी किडनी संबंधी बीमारी के लिए इलाज की खातिर सिंगापुर जाना चाहते थे। यहां पर वह किडनी ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हैं। इसका ज्यादा संभावना बन रही है। गौरतलब है कि इससे पहले समाजवादी पूर्व नेता अमर सिंह ने भी सिंगापुर में ही किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था। यह अलग बात है कि अमर सिंह का निधन हो चुका है। उनका किडनी ट्रांसप्लांट काफी सफल रहा था। उधर, तेजस्वी को राजज एवेन्यू की विशेष सीबीआई ने की अपना जवाब दायर करने के लिए और समय दिया है।

## लखीमपुर में बड़ा सड़क हादसा डीसीएम और बस में भीषण टक्कर, आठ यात्रियों की मौत



□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। लखीमपुर खीरी जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कई महिलाओं समेत आठ यात्रियों की मौत हो गई। घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिनमें से कई की हालत गंभीर बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार, लखीमपुर खीरी जिले में पीलीभीत बस्ती हाईवे पर शारदा पुल के पास बस और डीसीएम की आमने सामने की भीषण टक्कर हुई है। दर्दनाक हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। आठ लोगों की मौत भी हो गई है। मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों

को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं, घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसे के बाद चीख-पुकार मच गई।

वहीं, सूचना मिलने पर घटनास्थल पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर जायजा लिया है। जानकारी के मुताबिक, निजी बस बुधवार की सुबह आठ बजे के करीब धौरहरा से लखीमपुर के लिए रवाना हुई थी। वहीं डीसीएम लखीमपुर से बहराइच की ओर जा रही थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि निजी बस के परखच्चे उड़ गए, वहीं डीसीएम पलट गई। पुलिस मौके पर संबंधित जानकारी जुटा रही है। ग्रामीणों से भी पूछताछ जारी है।

## सम्मेलन को लेकर सपाइयों में जोश

फोटो : सुमित कुमार



□□□ 4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी का 9वां राज्य सम्मेलन राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में चल रहा है। अखिलेश यादव ने एक बार फिर नरेश उत्तम पटेल को सपा का दोबारा प्रदेश अध्यक्ष चुना है। साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि हम जब भी सत्ता में आएं किसानों के लिए काम करेंगे। सपा अध्यक्ष ने कहा कि सपा सरकार ने जो काम किया था भाजपा उससे आगे कुछ भी नहीं कर पाई है। वहीं सम्मेलन को लेकर सपा नेताओं में जबरदस्त जोश है। पार्टी कार्यालय से लेकर रमाबाई अंबेडकर मैदान तक सड़क के दोनों तरफ सपाईं झंडे लगाए गए हैं। जगह-जगह बैनर पोस्टर के साथ कटआउट भी लगाए गए हैं। सम्मेलन में लाखों की भीड़ है। खास बात यह है कि ज्यादातर कटआउट पर सिर्फ अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। कुछ में सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और आजम खां, प्रो रामगोपाल सहित अन्य स्थानीय नेताओं की तस्वीर लगी है। लेकिन ये कटआउट इस बात की तस्वीर कर रहे हैं कि यह सम्मेलन पूरी तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर केंद्रित है।

